



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62997

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4242/2026

विष्णु महतो

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: पीयूष पटेल, प्रदीप कुमार

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय सं० - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. श्री पीयूष पटेल के संक्षिप्त प्रपत्र को धारण करने वाले श्री आशीष कुमार, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्या को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत आवेदक की ओर से, मुकदमा अपराध संख्या 14 सन् 2024, अन्तर्गत धारा 8/21/23 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना टुटिहारी, जिला महाराजगंज में विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना हेतु दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और किसी छिपे उद्देश्य के कारण उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक के कब्जे से 100 मि.ली. बुप्रेनॉफीन इंजेक्शन बरामद होना कथित है। यह भी तर्क दिया गया कि सह-अभियुक्त सुरेन्द्र प्रसाद भारती को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विविध जमानत आवेदन संख्या 15207/2024 में दि० 08.07.2024 को पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक दि० 16.01.2024 से कारागार में बन्द है और वचन देता है कि यदि जमानत दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में मामलों की भारी लम्बितता को दृष्टिगत रखते हुए विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई सम्भावना नहीं है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा सलाम बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 3934/2005 (आर) में पारित निर्णय पर निर्भरता रखी, जिसमें बुप्रेनॉफीन की व्यावसायिक मात्रा ग्राम से मि.ली. में परिवर्तित करते हुए 66666.60 मि.ली. निर्धारित की गई है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों के अनुसार, आवेदक के कब्जे से 100 मि.ली. बुप्रेनॉफीन इंजेक्शन बरामद होना कथित है, जो व्यावसायिक मात्रा से काफी कम है। सह-अभियुक्त सुरेन्द्र प्रसाद भारती को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 15207/2024 में दि० 08.07.2024 को पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक दि० 16.01.2024 से कारागार में बन्द है।

6. तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित प्रकृति एवं साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त तथा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान को भी दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मैं इसे जमानत हेतु उचित प्रकरण पाता हूँ। अतः यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक- **विष्णु महतो** की गिरफ्तारी की दशा में उसे उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर रु० 50,000/- के व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों के प्रकटीकरण से विरत करने के लिए प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डरायेगा-धमकायेगा नहीं।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले की सुनवाई, (ii) आरोप विरचन एवं (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलेखन की नियत तिथियों पर व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, वह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिमत की अभिव्यक्ति नहीं माना जायेगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

26 मार्च, 2026

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”